पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International 1983-2023

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 26, अंक 1/2025

हम राजस्थानी : प्रदेश में रोजगार सृजन जरूरी

एमओयू पर सीधी निगरानी से पारदर्शी होगी निवेश प्रक्रिया

राजस्थान के बजट 2025-26 में रोजगार सृजन प्रमुख प्राथमिकता है। अगले एक वर्ष में 1.25 लाख सरकारी और 1.5 लाख निजी नौकरियां देने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 और 500 करोड़ के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा हुई है। पहली बार उद्यमी बनने वालों को सहयोग देने और 1,500 नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई है। जुलाई 2023 से जून 2024 के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार, राजस्थान की श्रम भागीदारी दर 64.8 प्रतिशत से 67.6 प्रतिशत हुई है।

राज्य में सर्वाधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र कृषि, वानिकी और मत्स्य, निर्माण और विनिर्माण हैं। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा में 228 लाख करोड़ का निवेश हुआ है फिर भी रोजगार की संभावनाएं कम हैं। पर्यटन,एसएमई विनिर्माण, कृषि प्रसंस्करण, वस्त्र, रत्न आभूषण और खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसलिए बजट में पर्यटन अवसंरचना के विस्तार के लिए 2975 करोड़ दिए गए है, जिसमें 10 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास, शेखावाटी हवेलियों का संरक्षण, 100 करोड़ का आदिवासी पर्यटन सर्किट और 220 करोड़ ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से अपेक्षाएं बढ़ी हैं, लेकिन समझौतों के क्रियान्वयन का प्रतिशत बहुत कम है। रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015 में 23.37 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, लेकिन केवल 10% ही क्रियान्वित हुए। इसी तरह, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में 12.53 लाख करोड़ के समझौते हुए, लेकिन मात्र 2% ही अमल में आए। नीमराना के जापानी औद्योगिक क्षेत्र में 'कट्स' द्वारा किए गए सर्वे में जल संकट, अनियमित विद्युत आपूर्ति और खराब अवसंरचना प्रबंधन जैसी समस्याएं निवेश में रुकावट पाई गईं।

प्रदेश में निवेश को कई कारक प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में निजी क्षेत्र का निवेश घट रहा है, कुछ कंपनियां विदेशों में स्थानांतरित हो रही हैं। बेहतर कारोबारी माहौल के कारण निवेशक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों को चुनते हैं। भारत में एफडीआई प्रवाह का स्तर भी गिर रहा है।

सरकार निवेश व रोजगार को बढ़ाने के लिए 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रही है। व्यापारिक सुधारों के तहत सिंगल विंडो सिस्टम में ऑनलाइन परमिशंस की संख्या बढ़ाकर 149 कर दी गई है। सरकारी विभागों की दक्षता मापने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक विकसित किया जा रहा है। निवेश के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी, मंजूरी की सुस्त प्रक्रिया, अवसंरचना की खामियों का समाधान करना होगा। एमओयू को तीन श्रेणियों (ए, बी, सी) में वर्गीकृत करने और 1,000 करोड़ से अधिक के समझौतों पर सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी सुनिश्चित करने से निवेश प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।

नई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन बढ़ाएगी, जबकि राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति, राज्य के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी। वैश्विक निवेश लाने के लिए राजस्थान को चाइना +1 रणनीति का लाभ उठाना चाहिए।

भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विदेशी निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं। राजस्थान-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी से इको-टूरिज्म और विरासत संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवसर खुल सकते हैं, जबकि यूएई के 52 बिलियन फूड कॉरिडोर से कृषि प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स में नए निवेश आ सकते हैं। आने वाले निवेशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 8 नए आईटीआई खोलने, 36 मौजूदा आईटीआई का आधुनिकीकरण करने और कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की है।

औद्योगिक क्षेत्रों के पास किफायती आवास भी श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। राजस्थान के ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन इनकी सफलता केवल कार्यान्वयन पर निर्भर है। उचित नीति समर्थन, बुनियादी ढांचे का विकास और नौकरशाही में सुधार करके राज्य वास्तव में निवेश को आर्थिक प्रगति में बदल सकता है।

प्रदीप एस महता

महामंत्री, कट्स इंटरनेशनल

इस अंक में...

- क्या हम तैयार नहीं कर रहे परजीवी? 4
- केंद्रीय बजट-2025-26 6
- राजस्थान बजट 2025-26 7
- 'नल से जल' मिशन में पिछड़े राजस्थान और मध्य प्रदेश 9
- महिलाएं बन रही है विकास की अगुवा 10

जनता की शक्ति से ही मिलता है सरकार को अधिकार! इसे कायम रखने के लिए आप हैं जिम्मेदार!!

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सहयोग से 'कट्स' जयपुर और सामाजिक विकास फाउंडेशन, धौलपुर के तत्वावधान में 17 जनवरी 2025 को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन श्री नवाब पैलेस, बाड़ी में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सामाजिक विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश कुमार परमार ने किया। उन्होंने आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षा फंड और बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में जानकारी दी। 'कट्स' के धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने उपभोक्ता संरक्षण में 'कट्स' के योगदान पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में भारतीय रिजर्व बैंक के फाइनेंशियल लिटरेसी विशेषज्ञ के.एन. वर्मा ने बैंकिंग प्रणाली, खातों की सुरक्षा और जमा धन पर रिस्क कवर के बारे में जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक के रमन गर्ग और आईसीआईसीआई बैंक के नरेन्द्र कुमार ने साइबर सुरक्षा, एटीएम उपयोग और नोमिनी पंजीकरण पर चर्चा की। कार्यशाला में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेम सागर ने साइबर अपराध से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया और हेल्पलाइन के उपयोग का सुझाव भी दिया।

'कट्स' के सह निदेशक दीपक सक्सेना ने बैंकों के निष्क्रिय खातों के बारे में और क्रेडिट/डेबिट कार्ड के नियमों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में बैंकिंग जागरूकता से सम्बन्धित वीडियो के माध्यम से भी संभागियों को जानकारी दी गई। इस आयोजन में सुरेंद्र सिंह परमार, रामदास तरुण, सतीश अग्रवाल, सुरेश दीक्षित, अतिराम सेमल, डॉ. योग्यता शाक्य सहित 80 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

बैंकिंग जागरूकता कार्यशाला में दी गई जमा पूंजी सुरक्षित रखने की जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 'कट्स' मानव विकास केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) में 21 फरवरी, 2025 को आयोजित जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के गोहर मेहमूद ने बैंकिंग से जुड़े विषयों की विस्तृत जानकारी दी।

'कट्स' के सह निदेशक दीपक सक्सेना ने प्रतिभागियों को बताया कि जिन बैंक खातों में लगातार 10 साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ, उन्हें निष्क्रिय मानकर आरबीआइ ने उस राशि को डेफ फंड में ट्रांसफर कर दी। आरबीआई द्वारा इस राशि से बैंक उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मुख्यवक्ता भारतीय रिजर्व बैंक के फाइनेंशियल लिटरेसी विशेषज्ञ के.एन.वर्मा ने बचत के तरीके, खातेदारों की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा और विभिन्न बैंक खातों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई-वॉलेट्स और बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के उपाय भी उपभोक्ताओं को समझाए। बीओबी बैंक सज्जनगढ़ के शाखा प्रबंधक संजय परमार ने ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और केवाईसी की जानकारी दी। आईसीआईसीआई बैंक के निलेश जैन ने स्मार्टफोन यूजर्स को बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए।

इस अवसर पर सहयोगी किसान उत्पादक संगठन के पदाधिकारी जालम सिंह, नरपत मईड़ा, हरलाल, भीमजी आमलियार और 'कट्स' से उदयलाल ने भी विचार रखे। कार्यशाला का संचालन सुरेश मिश्रा ने किया।

राज्यों को मिला पैसा खर्च नहीं हुआ

केंद्र सरकार की ओर से देशभर में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके लिए केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को वेलफेयर फंड भी जारी किया जाता है। लेकिन राज्य सरकारें इस फंड का अधिकतम हिस्सा खर्च ही नहीं कर पा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड से करीब एक लाख करोड़ रुपए का राज्य सरकारें उपयोग नहीं कर पाई।

राज्य सरकारों द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई राशि का जिक्र वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के बजट में भी किया है। पीएम आवास योजना में 13,111 करोड़, जल जीवन मिशन में 8,169 करोड़ अमृत योजना में 10,964 करोड़ स्वच्छ भारत-अर्बन में 10,406 करोड़ एवं सक्षम आंगनबाड़ी में 11,145 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। इसके अलावा भी कई मद ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकारें पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाई। राज्य सरकारों द्वारा पैसे का पूरा उपयोग नहीं करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।

(रा.प., 19.02.25)

जी का जंजाल बनी फसल बीमा

बीमा कंपनियों की अड़ंगेबाजी के कारण फसल खराबे के बावजूद किसानों को न तो समय पर क्लेम दिया जा रहा है और न ही बीमा क्लेम संबंधी जानकारी। स्थिति यह है कि रबी और खरीफ फसलों का बीमा होने के बावजूद किसान फसल खराबे का क्लेम लेने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों की पूरी मनमानी है। फसल खराबे के बावजूद किसानों को क्लेम देने के बजाय आपत्ति लगा दी जाती है। कई बार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किसान के पक्ष में रिपोर्ट देते हैं, फिर भी क्लेम जारी नहीं किया जाता। यही वजह है कि 16वीं विधानसभा के दो सत्रों में 60 प्रश्न केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हैं। प्रश्न लगाने वाले विधायकों की संख्या 40 से अधिक है। क्लेम अटकाने का खामियाजा कृषि विभाग भुगत रहा है। लेकिन मनमानी बीमा कंपनी की चलती है।

(रा.प., 02.01.25)

जल जीवन मिशन में फर्जीवाड़े का खेल

जलदाय विभाग की पेयजल परियोजनाओं में इंजीनियर और ठेकेदारों की मिलीभगत से हुए 55 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े पर जांच अधिकारी पर्दा डाल रहे हैं। परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के उपयोग की जांच में विजिलेंस और गुणवत्ता विंग की तीन कमेटियां ही जांच में हीलाहवाली कर रही है।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की जांच विंग में तैनात इंजीनियर ही जांच से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि जांच हुई तो 150 इंजीनियरों पर गाज गिर सकती है। फर्जी भुगतान के मामले में 150 इंजीनियरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। 55 करोड़ रुपए के अनियमित भुगतान मामले में गठित तीनों कमेटियों की जांच आने पर फर्जीवाड़े का पूरा खेल सामने आएगा।

(रा.प., 17.03.25)

किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा

राज्य विधानसभा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में वर्ष 2019 से 2023 के बीच बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। भाजपा विधायक केसाराम चौधरी के एक प्रश्न के उत्तर में सामने आया कि केवल मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में 13 हजार 858 फर्जी लोगों को 8.27 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई।

इनमें 13 हजार 750 लोग तो ऐसे हैं, जिनके गांव तक फर्जी लिखे हुए हैं। उनके नाम व मोबाइल नंबर भी फर्जी मिले हैं। किसान सम्मान निधि की यह राशि अलग-अलग किश्तों में जारी की गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। अब फर्जी लोगों से वसूली की जाएगी। यदि अन्य जिलों में भी जांच हो तो बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता है। *(रा.प.एवं दै.भा., 11.03.25)*

सामने आया करोड़ों रुपए का घोटाला

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में प्रदेश के 3200 ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) को सिंगल ओटीपी के जरिए भुगतान करने की ढील दी गई ताकि संविदाकर्मियों को समय पर भुगतान हो सके। लेकिन वीडीओ ने इसका फायदा उठाते हुए मानदेय की जगह फर्जी बिल लगाकर खुद के व अपने रिश्तेदारों के खातों में भुगतान कर लिया।

पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। करीब दस जिले ऐसे हैं जहां 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन हुआ। सबसे ज्यादा बाड़मेर में 16 करोड़ व नागौर में 12 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें बीडीओ ने 20 से ज्यादा ट्रांजेक्शन के माध्यम से सरकारी राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर ली। मामलों की आगे जांच की जा रही है तथा कई अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। *(दै.भा., 12.02.25)*

अनाज में पोषक तत्व हो रहे कम

रासायनिक खाद और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल धरती को बंजर बना रहा है। राजस्थान की मिट्टी भी इससे बीमार होती जा रही है। प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां जमीन में पोषक तत्वों की कमी नहीं है। यह कृषि वैज्ञानिकों की अध्ययन रिपोर्ट में सामने आया है।

इससे अनाज में पोषक तत्व लगातार कम होते जा रहे हैं। विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में की गई मिट्टी की जांच में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, जिंक, मैंगनीज, आयरन जैसे पोषक तत्वों की मात्रा कहीं कम तो कहीं ज्यादा मिली है। इससे लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। किसानों को मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग और फसल चक्र नहीं अपनाने से भी मिट्टी की उपजाउ क्षमता कम हो जाती है।

(रा.प., 09.01.25)

ग्रामीण विकास पर नहीं हुआ खर्च

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए हर साल बजट भरपूर दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 में बजट का जो संशोधित अनुमान रखा गया था, उसमें से 34.82 प्रतिशत राशि खर्च नहीं हो सकी।

संसदीय समिति ने पाया कि 2024-25 के संशोधित बजट में आवंटित 1,73,804 करोड़ रुपए के मुकाबले वास्तविक खर्च केवल 1,13,284 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए भी बजट में आवंटित राशि पूरी तरह खर्च नहीं हो पाई। *(रा.प., 28.03.25)*

कन्यादान योजना में पकड़ा फर्जीवाड़ा

प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 655 महिलाओं के नाम पर वर्ष 2019 से 2022 तक दो करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है।

अब तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 67 लाख रुपए की ही रिकवरी कर पाया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में भी मामला दर्ज कराया गया है। एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर प्राथमिक जांच में इसे प्रमाणित ठहराया है। करीब 67 लाख रुपए की वसूली भी हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि शेष राशि की वसूली के प्रयास चल रहे हैं। मामले की जांच अभी जारी है। *(दै.भा., 31.03.25)*

विधानसभा चलने के हैं नियम-कायदे

विधान सभा सत्र चलाने के लिए हर राज्य के अपने नियम- कायदे होते हैं और इन्हीं से विधानसभा चलती है। लेकिन राजस्थान विधानसभा में सत्र चलाने के नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है। अर्थात नियमों की पालना नहीं हो रही। इससे जनता के मुद्दे गौण हो रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा के एक साल में तीन सत्र और और तीनों को मिलाकर कम से कम 60 दिन बैठक होनी आवश्यक है। लेकिन हकीकत इससे उलट ही है। अब तो साल में दो सत्र भी मुश्किल से होते हैं और वह भी 60 दिन तो दूर 30 दिन से ज्यादा चल जाएं यही बड़ी चुनौती बन जाती है। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा सत्र चलाने वाले पांच राज्यों में राजस्थान का नाम नहीं है। 27 राज्यों के सर्वे में प्रदेश सदन चलाने में 8वें स्थान पर है।

(रा.प., 19.01.25 से 21.01.25)

सहकारी समितियों में हुआ घोटाला

प्रदेश की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में हुआ करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला विधानसभा में उठा। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने सहकारी समितियों में हुए घपले के बारे में पूछा कि क्या 37 अफसर 24 करोड़ रुपए की फसलें डकार गए?

उन्होंने नाम भी बताते हुए कहा कि घोटाले में शामिल अफसरों को फील्ड पोस्टिंग में लगा रखा है क्या? इनको कब तक हटाएंगे। इस पर सहकारी मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि इन अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी नहीं दी है। किसी अधिकारी का पदस्थापन है और आप संज्ञान में लाएंगे तो नियमानुसार परीक्षण कर कार्रवाई करेंगे। *(दै.भा., 08.02.25)*

खाद्य सुरक्षाः सामने आई सच्चाई

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक महीने आवंटित गेहूं में से प्रति माह हजारों और सालाना लाखों क्विंटल गेहूं डिपो से समय पर उठाव नहीं होने के कारण लैप्स हो रहा है। जितना गेहूं लैप्स हुआ यह गेहूं योजना के तहत चयनित 80 हजार लाभार्थियों को मिलता तो उन्हें फायदा होता।

विधानसभा में कोटा विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की ओर से योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक लैप्स हुए गेहूं को लेकर सवाल पूछा गया तो खाद्य मंत्री सुमित गोदारा की ओर से इस अवधि में लैप्स गेहूं की मात्रा को शून्य बताया है। जबकि खाद्य सुरक्षा योजना के विभागीय पोर्टल की पड़ताल में यह सच्चाई सामने आई है कि इसी अवधि में कुल 4 लाख 69 क्विंटल गेहूं लैप्स हुआ है। *(रा.प., 27.03.25)*

खाद्य सुरक्षाः वसूली में चुप्पी

खाद्य विभाग प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिवअप अभियान चलाकर योजना में शामिल 12 लाख अपात्रों के नाम हटाकर वाहवाही लूट रहा है, लेकिन इनसे 1500 करोड़ रुपए की वसूली पर विभाग चुप है। हालांकि सरकारी गेहूं उठाने वाले 6 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों से 100 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार कर्मचारियों से वसूली राशि को केंद्र सरकार ने वापस मांगा था। इसके बाद खाद्य विभाग के अफसरों में खलबली मच गई। हालांकि जितने नाम योजना से हटाए गए हैं उनसे 1500 करोड़ रुपए की वसूली होगी। इस राशि को भी केंद्र सरकार मांग सकती है। क्योंकि, खाद्य सुरक्षा में गेहूं केंद्र सरकार ही उपलब्ध करा रही है।

(रा.प., 19.03.25)

क्या हम तैयार नहीं कर रहे परजीवी?

चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस बी.आर.गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा 'क्या हम इस तरह परजीवियों का वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं? मुफ्त की योजनाओं के कारण लोग काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें बिना काम किए मुफ्त में राशन व धन मिल रहा है।'

पीठ बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस गवई ने कहा, दुर्भाग्य से मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं है। मुफ्त राशन या पैसा देने की जगह क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। देश के विकास में इन्हें भी योगदान देने का अवसर मिले।

(रा.प., 13.02.25)

आज भारत 'न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनियाभर के लोग भारत आना चाहते हैं और भारत को विस्तार से जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है, जहां हर दिन सकारात्मक खबरें बन रही हैं। जहां हर दिन नए रेकॉर्ड बन रहे हैं। 26 फरवरी को प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ। दुनिया इस बात से हैरान है कि कैसे करोड़ों लोग एक नदी के तट पर पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। दुनिया भारत के संगठन और नवाचार कौशल को देख रही है।

पीएम मोदी ने कहा, 'कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे आयुष प्रॉडक्ट्स और योग स्थानीय से वैश्विक हो गए हैं। भारत के सुपरफूड मखाना, मिलेट्स- श्रीअन्न भी स्थानीय से वैश्विक हो रहे हैं। दशकों तक, दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती रही, पर आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं वर्ल्ड-फोर्स हैं।'

(रा.प., 02.03.25)

भारत बनेगा उच्च शिक्षा का हब

भारत को दुनिया में उच्च शिक्षा का हब बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए सरकार ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा के इच्छुक विदेशी विद्यार्थियों के लिए दो स्पेशल केटेगरी के वीजा का ऐलाल किया है। गृह मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए 'ई-स्टूडेंट वीजा' और 'ई-स्टूडेंट एक्स वीजा' के लिए विदेशी विद्यार्थियों को सरकार के ' स्टडी इन इंडिया पर आवेदन करना होगा।

यह कार्यक्रम भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह 600 से ज्यादा संस्थानों के साथ साझेदारी करता है। सरकार ने विद्यार्थियों के साथ उनके परिजनों के लिए भी सुविधाओं का ऐलान किया है। 'ई-स्टूडेंट एक्स वीजा' उनके साथ आने वाले माता-पिता व जीवन साथी को मिलेगा। *(रा.प., 06.01.25)*

शांति और विकास के पथ पर कदम

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में शांति की स्थापना और विकास के लिए वर्ष 2025 के दौरान पांच अहम कदमों का खाका तैयार किया है।

इनमें सतत् विकास लक्ष्य, शांति और विश्वास, क्वांटम प्रौद्योगिकी , सहकारिता और ग्लेशियर संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर फोकस शामिल है। माना जा रहा है यह कदम वैश्विक चुनौतियों के समाधान में और सामूहिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

(रा.प., 02.01.25)-

अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण में भारत की वित्त वर्ष 2025-26 जीडीपी वृद्धि 6.3-6.8% के बी च रहने की उम्मीद जताई गई है। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में शिक्षा को देश की प्रगति में आठ प्रमुख स्तम्भों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 'भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति' बनाने का लक्ष्य रखा है।

सर्वेक्षण में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया गया है। महंगाई नियंत्रण में है। वित्त वर्ष 2025 के अप्रेल-दिसम्बर की अवधि में औसत महंगाई कम होकर 4.9% हो गई जो वित्त वर्ष 2024 में 5.4 प्रतिशत थी। सर्वेक्षण के अनुसार देश में खेती-किसानी के हालात बेहतर है। 2024 में खरीफ सीजन का खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

(रा.प., 01.02.25)

कृषि वानिकी नीति लाएगी सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वन हमारे जीवन का आधार है। हमें इन्हें बचाना है। इसके लिए राज्य में कृषि वानिकी नीति लाई जाएगी। उन्होंने अमृता देवी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में नदी, पहाड़, पेड़ों की पूजा की जाती है, इसलिए प्रकृति के साथ सहभागिता बढ़ानी चाहिए।

उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए राजस्थान को स्वस्थ और हरा-भरा बनाने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए प्रदेश में नदियों के सिकुड़ने, पहाड़ों के छोटे होने और वृक्षों के काटे जाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्र को 9.64 से 20 फीसदी तक लेकर जाना है। इसके लिए आगामी वर्षों में 50 करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य है। साथ ही एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम से स्थानीय किस्म विकसित करेंगे। *(रा.प., 22.03.25)*

ग्रामीण इलाकों में तेजी से घटी गरीबी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ग्रामीण इलाकों में पहली बार गरीबी शहरों के मुकाबले तेजी से घटी है और गरीबी की दर 5 प्रतिशत से नीचे आई, जो वर्ष 2022-23 में 7.2 प्रतिशत थी। शहरों में भी गरीबी की दर घटकर 4.09 प्रतिशत पर आ गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देशभर में गरीबी 4 से 4.5 प्रतिशत के बीच है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। गरीबी में कमी का कारण लोगों की आय में हुई बढ़ोतरी है। सबसे गरीब 5 प्रतिशत लोगों का ग्रामीण इलाकों में मासिक खर्च 1373 रुपए था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर1677 रुपए हो गया। शहरों में भी खर्च 2001 रुपए से बढ़कर 2376 रुपए हो गया। माना गया है कि ग्रामीण बुनियादी विकास ने आय बढ़ाने में मदद की है।

(रा.प. एवं दै.भा., 04.01.25)

लांच होगा अपना एआइ मॉडल

कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटलीजेंस (एआइ)की दुनिया में अमरीका और चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए भारत सरकार ने बड़ी पहल करते हुए स्वदेशी एआइ मॉडल बनाने पर काम शुरु कर दिया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि 10,370 करोड़ रुपए के इंडिया एआइ मिशन के हिस्से के रूप में खुद का बड़ा घरेलू भाषा मॉडल (लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम)तैयार किया जाएगा। इसे दस महीने में लांच कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया पिछले डेढ़ वर्ष से हमारी टीमें स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, प्रोफेसरों आदि के साथ मिलकर काम कर रही है। हम अपना खुद का आधारभूत मॉडल विकसित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। यह मॉडल भारतीय संदर्भ, भाषाओं, संस्कृति का खयाल रखेगा और पक्षपात से रहित होगा। *(रा.प., 31.01.25)*

केंद्रीय बजट-2025-26

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। इस बार बजट विकसित भारत के निर्माण व चहुंमुखी समृद्धि की दिशा में एक नई आशा की किरण लेकर आया है। यह भारत को आत्मनिर्भर व पूरी तरह सम्पन्न बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने वाला बजट है।

कृषि क्षेत्र है 'विकास का पहला इंजन'

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए 1,71,437 करोड़ रुपए का प्रावधान रखते हुए कृषि को 'विकास का पहला इंजन' माना है। उन्होंने स्वीकार किया है कि भारत को 'विश्व का खाद्य भंडार' बनाने में किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बजट में नौ नए मिशन कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि यह कृषि क्षेत्र की वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से 1.70 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, कीट प्रतिरोधी बीजों का विकास एवं प्रचार-प्रसार आदि पर भी खास जोर दिया गया है।

किसानों की आय बढ़ाना खास मकसद

बजट में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नौ प्रमुख कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा है। इनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता, सब्जी व फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, कपास उत्पादकता मिशन, उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन, बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रामीण समृद्धि और सुदृढ़ता कार्यक्रम, मत्स्य पालन क्षेत्र और असम में यूरिया संयंत्र हैं। इनमें राज्यों व कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बड़े पैमाने की किफायत का लाभ देते हुए किसानों के लिए संस्थागत तंत्र संगठित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र : देश बनेगा मेडिकल हब

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में 98,311 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इस मद में पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल15 फीसदी बजट बढ़ाया गया है। कैंसर व अन्य भीषण बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए जीवनरक्षक दवाएं सस्ती की गई हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ के लिए 'हील इन इंडिया' योजना शुरू की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा

डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई है। टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। बजट में पीएचसी और एसएचसी अस्पतालों के सुधार के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीण इलाकों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना

वित्त मंत्री ने बजट में 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाते हुए सूक्ष्म, लघु , मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करके राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करने की घोषणा की है। यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता व निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा तथा गुणवत्ता युक्त उत्पाद पर बल देगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन से 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है।

मिलेगा नए उद्यमियों को बढ़ावा

नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा इससे वेंचर कैपिटल निवेश प्रोत्साहित होगा। निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। भारत को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना शुरू होगी। सूक्ष्म, लघु , मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। स्टार्टअप के लिए ऋण का दायरा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया है। बैटरी उत्पाद और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा।

शिक्षा और कौशल से बढ़ेंगे कदम

बजट में शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इस बार शिक्षा में 2.39 फीसदी बजट बढ़ाया है। साथ ही कौशल विकास के लिए भी 0.52 फीसदी की वृद्धि की है। शिक्षा में तकनीक, रिसर्च व इनोवेशन को विशेष महत्व दिया गया है। मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग को खास तवज्जो मिली है। उच्च शिक्षा का बजट बढ़ने से कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। । इससे शिक्षा की गुणवत्ता व शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानकों के अनुसार संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था के लिए, शिक्षा विशेषज्ञ आवंटित बजट को नाकाफी मानते हैं।

ग्रामीण विकास को लगेंगे पंख

इस बार बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 5.75 फीसदी ज्यादा है। सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए 86 हजार करोड़ रुपए का आवंटन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपए निर्धारित है। यह पिछले साल से 58 फीसदी ज्यादा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए भी करीब इतनी ही राशि खर्च की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गुणवत्ता युक्त सस्ते आवास के लिए भी बजट में राशि बढ़ाई गई है।

नौकरीपेशा व माध्यम वर्ग को दी राहत

आम बजट नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आयकर स्लेब रेट में भी बदलाव किया गया है। इस राहत के लिए हर आयकरदाता कई सालों से इंतजार कर रहा था।

राजस्थान बजट 2025-26

राज्य विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट रखा। माना जा रहा है, यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने और प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

कृषि क्षेत्र को मिला बढ़ावा

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने खेती और किसानों के विकास के लिए बजट में 14,075.96 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अब सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे। इससे 70.36 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। दीर्घकालीन कृषि ऋण भी दिए जाएंगे। कृषि उपकरणों पर 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे एक लाख किसानों को फायदा मिलेगा। कृषि मंडियों की दशा सुधारने पर 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों को मोटे अनाज और इनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तायुक्त बीज के मिनी किट दिए जाएंगे।

सिंचाई व्यवस्था होगी बेहतर

बजट में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके लिए राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागू होगी। बजट में 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए 1,250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसानों को 50 हजार सौर पंप संयंत्र के लिए अनुदान दिया जाएगा।

शिक्षा से होगी रोजगार तक पहुंच

बजट में शिक्षा को रोजगार से जोड़ते हुए कुल मिलाकर कौशल पर ज्यादा जोर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेक्टर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेंगे। रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए सरकार युवाओं के लिए रोजगार नीति 2025 लाएगी। प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्केलिंग एंड कैरिअर काउंसलिंग की स्थापना होगी। 8 नई व 36 पुरानी आइटीआर का नवीनीकरण होगा। 12वीं पास कर चुके छात्रों को विशेषज्ञों से कैरिअर गाइडेंस मिलेगा।

स्कूली शिक्षा को मिलेगा प्रोत्साहन

बजट में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 40,992 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 50 प्राथमिक स्कूलों को आठवीं कक्षा तक व 100 स्कूलों को उच्च माध्यमिक विधालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। स्कूलों में लैब, क्लास रूम, कम्प्यूटर लैब और टॉयलेट आदि का निर्माण कराया जाएगा। गंगानगर में सैनिक स्कूल व पांच जिलों में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित होंगे। 15 हजार विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। कॉलेज शिक्षा के लिए 1,552 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में हैं।

ग्रामीण विकास को लगेंगे पंख

बजट में ग्रामीण विकास को खास महत्व दिया गया है। इसके लिए 24,925.02 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर 5,277.03 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत एक लाख 56 हजार आवासों का निर्माण करने , स्वच्छ भारत मिशन के तहत 85 हजार घरेलू शौचालय व 2500 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए गए है।

सेहत पर ध्यान, नब्ज पर रखा हाथ

बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कुल मिलाकर 20,324.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जयपुर स्थित एसएमएस व इससे जुड़े अस्पतालों में चिकित्सा व अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अपग्रेडेशन व भवन निर्माण के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा। गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित किया जाएगा।

मूलभूत सुविधाएं होंगी बेहतर

सरकार ने प्रदेश में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का प्रयास किया है। इसके लिए बजट में 17,383.81 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे राजमार्गों, जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों का तेजी से विकास हो सकेगा। इसमें से ग्रामीण सड़क निर्माण पर 7150 करोड़ रुपए एवं परिवहन व सड़क सुरक्षा पर 1,271.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी एवं ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए 8,761 करोड़ और ऊर्जा विकास के लिए 39,576 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रावधान बजट में है। गर्मी को देखते हुए 1000 ट्यूबवेल और 500 हैंडपंप भी लगाए जाएंगे। पीएम सूर्यघर योजना के तहत घरों पर सोलर पेनल लगा, उससे 150 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना है।

औद्योगिक समस्याएं दूर करने पर जोर

बजट में औद्योगिक विकास के लिए 3,121.45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश को लॉजेस्टिक हब बनाने, वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अहमियत देने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बजट में औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार की नीति, जिला स्तर पर पनप रहे उद्योगों को संबल देने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा अन्य समस्याओं के निदान से राज्य में निवेशक आकर्षित होंगे।

फ्यूल सरचार्ज के नाम पर छलावा

प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के साथ अलग तरह का छलावा हो रहा है। बिजली निगम बेस फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बेजा वसूली कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि किसी माह में ज्यादा वसूली गई राशि वापस बिलों में समायोजित नहीं की जाती।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसम्बर) संबंधी आदेश हाल ही में जारी हुआ है। सामने आया है कि 9 पैसे/यूनिट से तिमाही फ्यूल सरचार्ज निर्धारण हुआ, जबकि 57 पैसे/यूनिट दर से बेस फ्यूल सरचार्ज वसूल कर लिया गया। लिहाजा उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 48 पैसा/यूनिट राशि समायोजित करनी चाहिए। यह राशि मामूली नहीं, बल्कि प्रदेशभर का आंकड़ा देखें तो 1,319 करोड़ रुपए है, जिस पर उपभोक्ताओं का हक है। *(रा.प., 02.02.25)*

कुसुम योजना में राजस्थान अग्रणी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान कुसुम योजना में देश का अग्रणी राज्य रहा है। योजना में 5 हजार मेगावाट की सौ परियोजनाएं विकसित की जा रही है। उन्होंने कुसुम 2.0 की शुरुआत करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है, ताकि इस योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से राज्य में 5 लाख घरों में रूफटॉप प्लांट लगाए जा रहे हैं और अब तक लगभग 25 हजार घरों पर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए 2000 मेगावाट के नवीन सोलर पार्क की स्वीकृति से राज्य में सौर परियोजनाओं को गति मिलेगी। *(दै.भा., 22.01.25*

निःशुल्क बिजली योजना की गाइडलाइन

प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड 150 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार मुफ्त में सोलर प्लांट लगाएगी। वहीं, इससे ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को सरकार 17 हजार रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देगी। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी प्रतिमाह 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की गाइडलाइन में यह जानकारी दी गई है।

निःशुल्क बिजली के 3 मॉडल बनाए गए है। पहला मॉडल व्यक्तिगत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता के लिए है, वहीं दूसरा मॉडल 150 यूनिट से कम उपभोग करने वाले उपभोक्ता के लिए तथा तीसरा मॉडल अनरजिस्टर्ड उपभोक्ता के लिए है। अनरजिस्टर्ड को भी सोलर लगाने पर कई फायदे मिल सकेंगे। राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने उपभोक्ताओं व इंजीनियरों के लिए इस बाबत विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। *(दै.भा., 28.03.25)*

राइजिंग राजस्थानः सोलर प्लांट शुरू

राइजिंग राजस्थान में किए गए एमओयू के तहत नागौर के मूवाना में 1.89 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरु किया गया है। यह परियोजना सोलर 91 क्लीनटेक लिमिटेड ने विकसित की है।

कंपनी के निदेशक प्रतीक अग्रवाल का कहना है कि सरकार ने राज्य के बजट में ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट लागू किया है। इससे प्रदेश में रिन्युएबल और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश की संभावना बढ़ी है। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे सोलर प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी और बिजली की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन में सोलर सेक्टर में 28 लाख करोड़ रुपए निवेश के एमओयू किए गए हैं। अब इन एमओयू के तहत कंपनियां तेजी से अपने प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। *(दै.भा., 22.02.25)*

ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से होगा काम

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2032 तक बिजली की डिमांड दोगुनी हो जाएगी। हम ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह जानकारी देते हुए कहा कि तेजी से बिजली की खपत बढ़ने का कारण है कि देश में विभिन्न उत्पादों की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले 90 से 95 प्रतिशत तक खिलौनों का आयात करते थे, लेकिन यह आंकड़ा अब घटकर 60 प्रतिशत पर आ गया है। यानी स्थानीय उत्पादन बढ़ा है और बिजली की खपत भी। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए जारी निविदा में 4 लाख 12 हजार लाख टन की मांग आई। इसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी अन्य देशों की है। हमारे अभी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है या -24 घंटे नहीं है, ऐसे गांवों को सोलर से बिजली पहुंचाई जा सकती है। *(रा.प., 22.01.25)*

बिजली आखिर जाती कहां है?

भारत में पिछले 10 सालों में बिजली उत्पादन 65 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं बिजली की खपत 10 सालों में 60 प्रतिशत बढ़ चुकी है। वर्ष 2024 में खपत 5% बढ़ी, जबकि दुनिया में औसत वृद्धि 4.3% रही। अगले तीन वर्षों में भारत में सालाना 6.3% की दर से खपत बढ़ने का अनुमान है, जबकि दुनिया का औसत 4% ही रहेगा।

बिजली की खपत बढ़ क्यों रही है? इसका जवाब बेहद जटिल है। मौटे तौर पर बढ़ता औद्योगिकीकरण, घरों में बिजली उपकरणों की बढ़ती संख्या, एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिक वाहन इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बन रहे डेटा मेटर्स भी इसमें भूमिका निभाने लगे हैं। भारत में बिजली की क्या स्थिति है और दुनिया में क्या हो रहा है, इसे भास्कर की रिसर्च टीम ने दैनिक भास्कर के 2 मार्च 2025 के अंक में विस्तार से सामने रखा है। *(दै.भा., 02.03.25)*

प्रदेश में 'हर घर नल से जल' बेहाल

जल जीवन मिशन (जेजेएम) में 1.30 लाख से ज्यादा कनेक्शन होने पर ही प्रदेश के हर घर तक नल से जल पहुंच सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से बजट में जेजेएम की समय सीमा 2028 तक बढ़ाने के बाद भी प्रदेश में जलदाय विभाग की चुनौतियां कम नहीं हुई है।

प्रदेश में पिछले पांच साल में 56 फीसदी ग्रामीण घरों तक ही नल लग पाया है, जबकि 10 फीसदी घरों में योजना से पहले ही नल कनेक्शन थे। ऐसे में जेजेएम से पिछले पांच सालों में केवल 46 फीसदी ही कनेक्शन हुए हैं। अब तीन साल में 44 फीसदी यानी शेष 47 लाख घरों में पानी का कनेक्शन करना होगा। विभिन्न विवादों के चलते जेजेएम की गति बढ़ाना जलदाय विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। *(दै.भा., 03.02.25)*

बिछेगी शहर तक नई पाइपलाइन

बीसलपुर से जयपुर तक बिछी करीब 15 साल पुरानी पाइपलाइन में लीकेज आने की सूचना से ही शहर की 40 लाख की आबादी को चिंता सताने लग जाती है। अब सरकार ने जयपुर शहर के लोगों की इस चिंता को समाप्त करने के लिए 1886 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर से बीसलपुर तक नई पाइपलाइन बिछाने का बड़ा कदम उठाया है।

बीसलपुर से जयपुर तक 2300 एमएम की नई पाइपलाइन बिछने के बाद अगले 30 साल तक पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। यह काम वर्ष 2029 तक पूरा हो जाएगा। जलदाय विभाग के इंजीनियरों के मुताबिक अभी पुरानी पाइपलाइन से जयपुर शहर को प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर पानी मिल रहा है। नई पाइपलाइन से जयपुर शहर को प्रतिदिन 70 करोड़ लीटर पानी मिलेगा। *(रा.प., 21.02.25)*

भूजल के लिए कर्मभूमि से जन्मभूमि

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को ईआरसीपी-पीकेसी लिंक परियोजना से पेयजल व सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के तहत जल उपलब्धता तय की जा रही है। वहीं माही बांध से बांसवाड़ा-डूंगरपुर को पेयजल व सिंचाई के लिए योजना शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री डूंगरपुर के खड़गदा गांव में नदियों के संरक्षण व संवर्धन हेतु आयोजित श्रीरामकथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के 40 हजार गांवों में जल संचय के कार्य किए जा रहे हैं। *(दै.भा., 02.01.25)*

प्रदेश की 11 नदियों को जोड़ा जाएगा

प्रदेश की 11 नदियों को जोड़ने से पूरा राजस्थान हरा-भरा हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। यह जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने डूंगरपुर जिले के खड़गदा में आयोजित रामकथा के दौरान दी है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि नदियों को जोड़कर सूखे क्षेत्रों को हरा-भरा किया जाए। उसी दिशा में काम करते हुए 11 नदियों को जोड़कर राजस्थान को हरा-भरा बनाएंगे। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मोरन नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। गांव वालों ने जन सहयोग से इसका पुनरुद्धार कर एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। *(रा.प., 05.01.25)*

अमृत-2.0 प्रोजेक्ट में होंगे ये काम

अमृत-2.0 योजना में शहरी घरों में अब स्मार्ट पानी के मीटर लगेंगे, ताकि उपभोक्ता को उपयोग किए पानी का चार्ज ही देना पड़े और छीजत कम हो व विभाग को पूरा राजस्व मिले। इसके साथ ही नए पंप हाउस व टंकिया बनाई जाएंगी। इससे पाइपलाइन के टेल एंड तक पूरे प्रेशर से पानी मिले।

इसके साथ ही दूषित पानी की सप्लाई वाले इलाकों में पाइपलाइन भी बदली जाएगी। प्रदेश के 183 शहर व कस्बों में अमृत-2.0 प्रोजेक्ट में एक-एक जोन (क्षेत्र) में 24 घंटे पानी की सप्लाई का सिस्टम विकसित कर उपभोक्ताओं को सुविधा दी जाएगी। यह काम फिलहाल जयपुर, कोटा, उदयपुर, नवलगढ़, पाली, आबूरोड, लक्ष्मणगढ़ सहित बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा। *(दै.भा., 10.03.25)*

रिचार्ज से ज्यादा भू-जल दोहन

प्रदेश की जमीन में जितना पानी रिचार्ज हो रहा है, उससे 150 फीसदी ज्यादा दोहन किया जा रहा है। इस आंकड़े ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और अब सभी पंचायतों को अटल भू-जल योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में 11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं।

इस योजना से 17 जिलों की केवल 1132 पंचायतें ही जुड़ी हुई है। यहां फार्म, तालाब, एनीकट, वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इससे कुछ जगह भू-जल गिरावट में कमी आई है। इस प्रोजेक्ट पर जो पैसा खर्च होगा, उसमें से केंद्र सरकार करीब 20 प्रतिशत इंसेटिव के रूप में देगी। इसी कारण भू-जल मंत्री ने केंद्र सरकार को प्रदेश की सभी पंचायतों को जोड़ने का आग्रह किया है। *(रा.प., 11.02.25)*

'नल से जल' मिशन में पिछड़े राजस्थान और मध्य प्रदेश

देश में पिछले छह साल के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 12.90 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन दिए गए। इसमें राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल जेजेएम को लागू करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। देश के 11 राज्यों में शत प्रतिशत ग्रामीणों को नल से जल आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

जल संसाधन से जुड़ी स्थायी समिति ने लोकसभा में पेश की रिपोर्ट में यह तस्वीर उजागर की है। रिपोर्ट में समिति ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि मिशन पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की समस्याओं पर गौर किया जाए। दरअसल 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा से अब तक करीब 3.08 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 13 करोड़ परिवारों तक नल से जल के कनेक्शन पहुंचाए गए। *(रा.प., 18.03.25)*

महिलाएं बन रही है विकास की अगुवा

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने कहा ---है कि देश अब 'महिला विकास' से आगे बढ़कर 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' की ओर जा रहा है। यानी, अब महिलाएं केवल विकास का हिस्सा नहीं, बल्कि विकास की अगुवा बन रही है। हमें अपनी बहन बेटियों को शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना होगा।

उन्होंने छतरपुर के बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेते हुए यह विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाएं सबल होंगी तो समाज और देश भी सबल होगा। हमारे देश के संतों ने हमेशा समाज को सही दिशा दिखाई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि समाज को अब यह संकल्प लेना चाहिए मंदिर की दान पेटियों का पैसा बेटियों के भलाई और उनके विकास पर खर्च किया जाए। इस कार्यक्रम में 251 बेटियों की शादी हुई, जिनमें से 108 जनजातीय वर्ग की बेटियां हैं।

(दै.भा., 27.02.25)

विज्ञान- तकनीक में आगे बढ़ी बेटियां

देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र भी इससे अधूरा नहीं है। विज्ञान और तकनीक में कैरियर बनाने के लिए केंद्र सरकार की विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। इसमें 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 300 जिलों की 80 हजार से अधिक बेटियों को लाभ हुआ है। यह संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

केंद्र सरकार इस योजना में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी छात्राओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कार्यक्रम में 250 से भी अधिक प्रमुख संस्थानों को शामिल किया है। इसमें विश्वविद्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सीएसआइआर लैब्स और अन्य संगठन शामिल हैं। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के शीर्ष लाभार्थियों में उत्तर प्रदेश प्रथम,महाराष्ट्र दूसरे, गुजरात तीसरे, राजस्थान चौथे व मध्यप्रदेश पांचवे स्थान पर है। *(रा.प., 21.03.25)*

स्कूली शिक्षा में अब महिला राज

भारत में पहली बार सभी प्रकार के स्कूली शिक्षकों में महिला शिक्षकों की संख्या पुरुषों से 53.3 प्रतिशत अधिक हो चुकी है। 2023-24 के लिए जारी यूडीआइएसई प्लस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफोरमेशन सिस्टम फॉर एजूकेशन) रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला शिक्षकों का यह अब तक का सबसे अधिक अनुपात है।

वर्ष 2018-19 में स्कूल में पुरुष शिक्षक आधे से ज्यादा थे। तब 94.3 लाख शिक्षकों में 47.16 लाख (50.01 प्रतिशत) पुरुष थे। महिलाओं की यह बढ़त स्कूली शिक्षा तक ही सीमित है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों में महिला शिक्षक तेजी से बढ़ रही हैं लेकिन सरकारी स्कूल और उच्च शिक्षा में अब भी पुरुषों का वर्चस्व कायम है। *(रा.प., 07.01.25)*

महिलाओं ने जुटाई स्टार्टअप फंडिंग

भारतीय टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम अब महिला संस्थापकों वाली कंपनियों द्वारा जुटाए गए ऑल टाइम फंडिंग के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। हाल ही जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस क्षेत्र में अब तक कुल 26 बिलियन डॉलर जुटाए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 7000 से अधिक महिलाओं के नेतृत्व वाले एक्टिव स्टार्टअप हैं, जो देश में सभी एक्टिव स्टार्टअप का 7.5 प्रतिशत है। प्रमुख स्टार्टअप रिसर्च और एनालिटिक्स फर्म ट्रैक्शन के आंकड़ों के अनुसार इन स्टार्टअप ने सामूहिक रूप से 26.4 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जिसमें 6.3 बिलियन डॉलर फंडिंग के साथ 2021 सबसे ज्यादा फंडिंग वाला वर्ष रहा। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप की संख्या और अब तक जुटाए फंडिंग दोनों में बैंगलुरू सबसे आगे है। इसके बाद मुंबई और दिल्ली एनसीआर का स्थान है। *(रा.प., 10.03.25)*

महिलाएं स्वस्थ तो बढ़ेगी जीडीपी

महिलाएं स्वस्थ रहे और वे पूरी क्षमता से काम करें, तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी हो सकती है। विश्व आर्थिक मंच(डब्ल्यूईएफ)और मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के नए शोध में बताया गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए, तो 2040 तक दुनियाभर में जीडीपी में सालाना 34.60 लाख करोड़ की बढ़ोतरी संभव है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अपने जीवन का 25% से अधिक हिस्सा हराब स्वास्थ्य में बिता रही है। महिलाओं के मां बनने से लेकर जीवन के अलग-अलग पड़ाव पर नौ प्रकार के स्वास्थ्य स्थितियों से गुजरना पड़ता है। रिपोर्ट में महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

(दै.भा., 22.01.25)

महिलाएं बन सकेंगी सशक्त व समृद्ध

प्रदेश के 2025-26 के बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार कालीबाई योजना के तहत 35 हजार स्कूटी वितरित की जाएंगी, राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ा जाएगा। पत्नी के नाम से या संयुक्त नाम से खरीदी 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को एक लाख रुपए का ऋण 1.5 प्रतिशत की दर पर मिलेगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत अंतिम पांच महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अब 5 दिन दूध मिलेगा। इसके अलावा भी बजट में महिलाओं को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

(रा.प.एवं दै.भा., 20.02.25)

सड़क हादसे में घायलों को मुफ्त इलाज

पूरे देश में मार्च 2025 से सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को डेढ़ लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इसके लिए नोडल ऐजेंसी का काम करेगा। राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में संशोधन किया जा चुका है।

दुर्घटना के बाद घायलों को पुलिस या कोई आम नागरिक या संस्था जैसे ही अस्पताल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस भी जमा नहीं करनी होगी।

घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं हो, अस्पताल उसकी पूरी देखरेख करेंगे। अस्पताल चाहे निजी हो या सरकारी पैनल में रजिस्टर हो या नहीं, उन्हें कैशलेस इलाज देना होगा। सूत्रों का कहना है कि डेढ़ लाख रुपए तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में एनएचएआइ काम करेगा यानी इलाज के बाद मरीज या उनके परिजनों को डेढ़ लाख तक की रकम का भुगतान नहीं करना है।

(दै.भा., 04.03.25)

सड़क सुरक्षा में एआई का उपयोग

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल की 21वीं बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि दुर्घटनाओं को रोकना और उनसे मानव जीवन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा के लिए साझा जिम्मेदारी से काम करें और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

उन्होंने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर सड़क निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स और गड्ढों की निरंतर पहचान कर उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार करने, राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए। परिवहन विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि राजस्थान 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान लागू करने और सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल लांच करने वाला देश का पहला राज्य है। *(रा.प., 12.02.25)*

हाईवे दे रहे हैं हादसों को न्योता

जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर भांकरोटा अग्निकांड हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की उदासीनता के कारण जयपुर जिले में जयपुर-दिल्ली, जयपुर-आगरा, जयपुर सीकर राजमार्ग 50 से अधिक कट ऐसे हैं जो भांकरोटा जैसे हादसे को न्योता दे रहे हैं।

हाईवे पर शहरों कस्बों में तिराहों पर छोटे कट पर कहीं भी संकेतक नहीं है। उक्त राजमार्गों पर कई ऐसे कट मिले जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। वाहन चालक भी जान की परवाह किए बिना इन कट से आवाजाही कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। मसलन जयपुर से दौसा के बीच ही हाईवे पर 31 कट और चौराहे बने हुए हैं जिन पर दिनभर वाहनों की क्रोसिंग होती है। ऐसे ही अन्य राजमार्गों पर भी इस प्रकार के कट पर भी संकेतक और रोड लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। *(रा.प., 08.01.25)*

23 गुड सेमेरिटन को किया सम्मानित

जयपुर में भांकरोटा में 20 दिसंबर को डीपीएस कट के पास एक एलपीजी गैस टैंकर और कंटेनर की टक्कर के बाद गैस का रिसाव होने से आग लग गई थी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए थे और वाहन जलकर नष्ट हो गए थे। इस भीषण अग्निकांड में घायल लोगों की सहायता करने वाले 23 गुड सेमेरिटन को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया।

इन सभी लोगों को दस-दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। उनके साहस और मदद की बुकलेट एवं डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है। इससे पहले 25 गुड सेमेरिटन को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी यू.आर.साहू सम्मानित कर चुके हैं। इनमें से दो एम्बुलेंस कर्मियों को छोड़कर बाकी 23 लोगों को सरकार ने भी 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इन्होंने निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। *(रा.प., 19.03.25)*

बच्चे चला रहे हैवी मोटरसाइकिलें

जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी एवं अभिभावकों की छूट के कारण किशोर उम्र के बालक-बालिकाएं सड़कों पर भारी दुपहिया वाहन दौड़ा रहे हैं। ज्यादातर किशोर न तो हेलमेट लगाते है न ही परिवहन विभाग से लाइसेंस लेते हैं। चिंता की बात है, किशोर परिजनों से जिद करके 350 सीसी वाले वाहन लेकर स्कूल और बाजारों में मिल जाते हैं।

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 4 (1) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बालक सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बड़ी बाइक थमाने वाले अभिभावकों को परिवहन विभाग के नियमों की जानकारी तक नहीं है। जबकि अभिभावकों को बच्चों को वाहन थमाने से पहले नियमों की जानकारी रखनी चाहिए। नियमों की जानकारी नहीं होने और बच्चों को भारी वाहन चलाने की छूट देने वाले कई घरों के चिराग बुझ गए।

(रा.प., 23.01.25)

उपभोक्ता फैसले

डिफेक्टिव स्लीपर बेचना महंगा पड़ा

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में सुनीता कुमावत ने एरो क्लब (वुडलैंड इंडिया) के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उनके वकील द्वारा बताया गया कि परिवादिया ने विपक्षी पार्टी के यहां से 1836 रुपए में स्लीपर की एक जोड़ी खरीदी थी। खरीदने के एक महीने बाद ही स्लीपर में डिफेक्ट आना शुरू हो गया। स्लीपर का कलर फेड़ हो गया और वह जगह- जगह से फट गया। वह किसी भी तरह पहनने के लायक नहीं रहा। स्लीपर पर 90 दिन की गारंटी दी गई थी। परिवादिया ने विक्रेता एरो क्लब (वुडलैंड इंडिया) से इसकी शिकायत की तो वह टालमटोल करने लगा। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी विक्रेता ने स्लीपर नहीं बदली और न ही उसकी कीमत वापस की है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्टिव स्लीपर बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। आयोग ने विक्रेता एरो क्लब (वुडलैंड इंडिया) को आदेश दिया कि वह सुनीता कुमावत को 45 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करें। साथ ही निर्देश दिया कि वह उन्हें स्लीपर की कीमत 1836 रुपए भी परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस दें। *(दै.भा., 26.01.25)*

भारी पड़ा फिल्म के बीच विज्ञापन दिखाना

फिल्म थियेटर में फिल्म के दौरान पहले दिखाए जाने वाले लंबे विज्ञापनों से परेशान बेंगलुरु के अभिषेक एमआर ने पीवीआर और आइनॉक्स के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में परिवाद दाखिल कर 65 हजार रुपए का मुआवजा जीता है। मामले के अनुसार अभिषेक 2023 में विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने उक्त थियेटर में गए थे। फिल्म से पहले दिखाए गए लंबे विज्ञापनों के कारण फिल्म देरी से शुरू हुई। उन्होंने दावा किया कि इससे उसके लगभग 30 मिनट बर्बाद हो गए और इससे वे एक जरूरी अपॉइंटमेंट में नहीं पहुंच सके, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता अदालत ने माना कि हर व्यक्ति का समय मूल्यवान है। थियेटर में गैर जरूरी विज्ञापन देखने के लिए 25-30 मिनट काफी लंबा समय है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके शेड्यूल काफी व्यस्त होते हैं। इस अनोखे मामले में उपभोक्ता अदालत ने अभिषेक के पक्ष में फैसला सुनाया और फिल्म थिएटर चेन को आदेश दिया कि वह उन्हें 65,000 रुपए का मुआवजा अदा करें। *(रा.प., 21.02.25)*

कंपनियां नहीं कर रही पैकेट पर एक्सपायरी डेट लिखने के नियमों की पालना

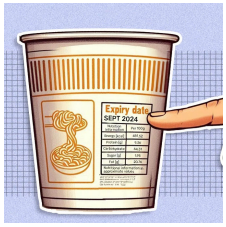

एक्सपायरी डेट के बाद किसी भी खाद्य उत्पाद का सेवन हानिकारक हो सकता है। लेकिन कंपनियां खाद्य सामग्री पर एक्सपायरी डेट लिखने के नियमों का सही रूप से पालन नहीं कर रही है।भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों में उत्पाद पर एक्सपायरी डेट 3 मिमी फॉन्ट में नीले, काले या सफेद रंग से लिखनी अनिवार्य है। जिसे ग्राहक आसानी से देख और पढ़ सके।

साथ ही पैकेट पर बार कोड़ भी जरूरी है, जिसमें उपभोक्ता को खाद्य उत्पाद की सारी जानकारी मिले। लेकिन देखने में आया है कि कई उत्पादों पर एक्सपायरी या यूज बाय डेट छुपे हुए तरीके से लिखी होती है या आसानी से पढ़ने में नहीं आती हैं। उत्पाद की सारी जानकारी मोटे अक्षरों में पैकेट के दिखने-पढ़ने लायक जगह पर लिखी होनी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों का दावा है कि लेबलिंग, चेतावनी व एक्सपायरी डेट के नियमों के उल्लंघन पर संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

ग्राहक नियमों का उल्लंघन देखे तो जिला सचिवालय में फूड सेफ्टी कमिश्नर को शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम या जागो ग्राहक जागो पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। लेबल में गड़बड़ी के आरोप साबित होने पर निर्माता, दुकानदार, रिटेलर व अन्य पर 10 हजार से लेकर 3 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। *(दै.भा., 02.03.25)*

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)